माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष

दीवानी *विविध*

राज पॉल - याचिकाकर्ता।

बनाम

प्रशासक, नगरपालिका समिति, मंडी डबवाली और अन्य, *उत्तरदाता।*

1967 की दीवानी रिट संख्या 1317

18 फरवरी, 1970।

पंजाब नगरपालिका अधिनियम (1911 का III) धारा 39- 40 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले नगरपालिका कर्मचारी - नगरपालिका अध्यक्ष क्या ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को बर्खास्त करने या समाप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं- आरोप-पत्र की सेवा करते समय प्राधिकारी को दंडित करना क्या उसमें सजा का प्रस्ताव कर सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि नगर समिति के अध्यक्ष 40 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले नगरपालिका कर्मचारी की सेवाओं को बर्खास्त करने या समाप्त करने की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। निलंबन, आरोप-पत्र दाखिल करने और जांच करने की कार्रवाई नगरपालिका समिति द्वारा एक बैठक में की जानी होती है। राष्ट्रपति स्वयं ऐसे कर्मचारी को निलंबित नहीं कर सकते या आरोप-पत्र दायर नहीं कर सकते या जांच नहीं कर सकते। (पैरा 3)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सजा देने वाला प्राधिकारी, आरोप-पत्र की सेवा करते समय, सजा का प्रस्ताव नहीं कर सकता है जैसे कि आरोप साबित हो गए हैं। (पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि *प्रतिवादी संख्या 12 के आदेशों को रद्द करते हुए* प्रमाणपत्र, परमादेश *या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की रिट जारी की जाए।* 1 *और नहीं।* 3, *दिनांक* 19 सितम्बर, 1966 और *14 अप्रैल 1967 क्रमशः*।

याचिकाकर्ता की ओर से चौधरी रूप चंद, वकील।

एम. के. महाजन, वकील, उत्तरदाता 1 और 2 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति बल राज तुली-याचिकाकर्ता राज पॉल को पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत डबवाली नगरपालिका समिति का स्वच्छता निरीक्षक-सह-खाद्य निरीक्षक नियुक्त किया गया था, और 1956 में उपायुक्त, हिसार की मंजूरी मिलने के बाद उस पद पर उनकी पुष्टि की गई थी। 18 मई, 1966 को, याचिकाकर्ता ने उस तारीख से 21 मई, 1966 तक छुट्टी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो एक चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित था, लेकिन इससे पहले कि इसे मंजूरी दी गई, उन्होंने कार्यालय छोड़ दिया। इस आवेदन को उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने 23 मई, 1966 को एक और आवेदन भेजा, जिसमें 31 मई, 1966 तक अपनी छुट्टी बढ़ाने की मांग की गई, जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया गया था। फिर भी 5 जून, 1966 तक छुट्टी के विस्तार के लिए एक और आवेदन 28 मई, 1966 को उनके द्वारा भेजा गया था। 3 जून, 1966 को याचिकाकर्ता ने 6 जून, 1966 से 30 जून, 1966 तक छुट्टी के विस्तार के लिए एक और आवेदन दिया। इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। नगर समिति के अध्यक्ष देस राज गर्ग ने पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 35 के तहत कार्य करते हुए याचिकाकर्ता को 26 मई, 1966 को इस कारण से निलंबित कर दिया कि वह खुद अनुपस्थित रहे और अपनी छुट्टी मंजूर किए बिना बाहर चले गए और इस तरह नियमों का उल्लंघन किया। इसके अलावा, वह खुद को पुलिस की जांच से बचा रहा था। 7 जून, 1966 को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आरोप-पत्र तैयार किया गया और इसे 25 जून, 1966 को नगरपालिका कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंप दिया गया। यह आरोप-पत्र हिन्दी में है और अंग्रेजी में इसका निशुल्क अनुवाद निम्नानुसार है -

एक. पीठ ने कहा, 'आप इसे मंजूरी दिए बिना छुट्टी पर चले गए. इसलिए, आपको यह बताना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया और अपना पूरा पता क्यों नहीं दिया।

दो. आपने स्टेशन छोड़ने की अनुमति प्राप्त नहीं की, जबकि शहर छोड़ने से पहले नगरपालिका समिति को सूचित करना आपके लिए अनिवार्य था।

तीन. आपने निलंबन आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अब तक प्रभार नहीं लिया है जिसके कारण काम प्रभावित हो रहा है जिसके लिए आप पूरी तरह से उत्तरदायी हैं।

चार. यह भी पता चला है कि आपके खिलाफ पुलिस जांच की जा रही है और उस जांच से बचने के लिए आपने खुद को अनुपस्थित कर दिया।

इसलिए, आपको यह बताना चाहिए कि आपकी सेवाओं को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता है। चार्जशीट के हर आइटम का जवाब चार्जशीट की प्राप्ति से तीन दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह माना जाएगा कि आप कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं और आपकी गलती है।

याचिकाकर्ता ने 30 जून, 1966 को आरोप पत्र का जवाब भेजा। याचिकाकर्ता के निलंबन के संबंध में मामला 7 अगस्त, 1966 को आयोजित अपनी बैठक में नगरपालिका समिति के समक्ष रखा गया था, और 26 मई, 1966 को राष्ट्रपति द्वारा किए गए निलंबन के आदेश की पुष्टि की गई थी। 2 सितंबर, 1966 को याचिकाकर्ता ने डिप्टी कमिश्नर, हिसार के समक्ष नगर समिति, डबवाली द्वारा पारित निलंबन आदेश के खिलाफ 7 अगस्त, 1966 के संकल्प संख्या 6 के तहत अपील दायर की। नगरपालिका समिति के अध्यक्ष ने 3 सितंबर, 1966 को याचिकाकर्ता को एक पत्र जारी

किया जिसमें कहा गया था -

> उन्होंने कहा, 'आरोपपत्र के जवाब मिल गए हैं और उन पर गौर किया गया है. जवाब विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मामले का समर्थन करने के लिए सबूतों और दस्तावेजों के साथ 6 सितंबर, 1966 को सुबह 11.00 बजे नगरपालिका कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 3 सितंबर, 1966 और 15 सितंबर, 1966 को जांच की। पूर्व तिथि पर, याचिकाकर्ता से पूछा गया था कि वह छुट्टी प्राप्त किए बिना और स्टेशन की छुट्टी मंजूर किए बिना कार्यालय क्यों छोड़ दिया। उस प्रश्न के उत्तर में, याचिकाकर्ता ने एक बयान दिया जो उर्दू में दर्ज है और जिसका अंग्रेजी में मुफ्त अनुवाद निम्नानुसार है: –

> उन्होंने कहा, 'मेरे पास आरोपपत्र के जवाब में मेरे द्वारा सौंपे गए जवाब और उपायुक्त के समक्ष मेरे द्वारा की गई अपील के संबंध में ठोस सबूत हैं। मैं समिति के सभी सदस्यों के समक्ष एक बैठक में इन सभी मामलों के संबंध में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि मुझे पूर्ण न्याय मिल सके। मुझे आपके हाथों न्याय पाने का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने पार्टी गुट के आधार पर मेरे खिलाफ झूठा मामला गढ़कर मुझे और मेरे बच्चों को भुखमरी के लिए मजबूर करने की योजना बनाई है। आपने अपने ही लोगों को सबूत देना सिखाया और मेरे खिलाफ हलफनामा दिया और मेरे खिलाफ मामला बनाया। अंत में, मैं पुन निवेदन करता हूं कि मुझे जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और जो भी जांच मुझसे की जानी है। मैं इसे समिति की बैठक में पेश करूंगा, जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे।

राष्ट्रपति ने कोई सबूत दर्ज नहीं किया और 15 सितंबर, 1966 को एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का बयान 9 सितंबर को दर्ज किया गया था। 1966. ने खुलासा किया कि उनके पास बचाव करने के लिए कोई बचाव नहीं था और तदनुसार उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही थे। यह रिपोर्ट उर्दू में है, जिसका अंग्रेजी में निशुल्क अनुवाद निम्नानुसार है:-

> अदालत ने कहा, 'उनके द्वारा पेश किए गए बीमारी के प्रमाण पत्र को इस आधार पर वास्तविक नहीं माना जा सकता कि उन्होंने सत्र अदालत में इसी तरह का आवेदन दायर किया था और खुद को अंतरिम जमानत पर रिहा कराया था. बाद में उनकी बीमारी के संबंध में वास्तविक प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहने पर सत्र न्यायालय द्वारा जमानत बांड रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह साबित करता है कि राज पॉल वास्तव में बीमार नहीं थे और

Z'i**

छुट्टी देने के लिए उनके आवेदन वास्तविक नहीं थे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा किया था, वह उन दिनों खुद को जमानत पर रिहा करने की कोशिश कर रहे थे और बिल्कुल बीमार नहीं थे। इसका मतलब है कि उन्होंने समिति में झूठे आवेदन दायर किए और इस तरह उस पर धोखाधड़ी की।

वर्तमान में उसके खिलाफ पुलिस में अवैध रिश्वत के संबंध में एक मामला दर्ज है, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट से स्पष्ट है। उन्हें उस मामले में भी गिरफ्तार किया गया था और अब वह जमानत पर हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में उनके खिलाफ कुछ आवेदन पहले ही प्राप्त हुए थे और इसलिए आम जनता के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है।

परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर समझाया गया है। मेरा विचार है कि समिति और जनता के हित में ऐसे व्यक्ति को सेवा में बनाए रखना वांछनीय नहीं है। इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है और उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को तैनात किया जा सकता है ताकि समिति का काम सुचारू रूप से चल सके।

राष्ट्रपति की यह रिपोर्ट 19 सितंबर को हुई म्यूनिसिपल कमेटी की बैठक में रखी गई थी। 1966. एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की रिपोर्ट सहित पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित किया गया था। तदनुसार, नगरपालिका समिति और जनता के हित में, याचिकाकर्ता की सेवाओं को 19 सितंबर, 1966 की दोपहर से समाप्त कर दिया गया था, और यह संकल्प लिया गया था कि उपायुक्त की मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। समिति के पांच सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनकी सेवाओं को समाप्त करने के नगरपालिका समिति के इस आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की। हिसार। निलंबन के आदेश के खिलाफ और उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश के खिलाफ उनकी अपील ों को उप-विभागीय अधिकारी द्वारा सुना गया और 14 अप्रैल, 1967 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 26 जून, 1967 को इस न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका दायर की।

2. रिट याचिका की वापसी नगरपालिका समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वयं और नगरपालिका समिति की ओर से दायर की गई है।

3. दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद। मेरी राय है कि नगरपालिका समिति के अध्यक्ष द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित करने, उस पर आरोप पत्र दायर करने, जांच करने और रिपोर्ट बनाने में अपनाई गई पूरी प्रक्रिया इस विषय पर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के खिलाफ थी। अधिनियम की धारा 39 के तहत, नगर पालिका के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति नगरपालिका समिति में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। सेनेटरी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट नियम हैं जो पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 21 अप्रैल, 1915 और पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 22893 दिनांक 30 जुलाई, 1930 में निहित हैं। नियम 5 के अनुसार, स्वच्छता निरीक्षक की नियुक्ति नगरपालिका समिति द्वारा की जानी है। म्यूनिसिपल कमेटी डबवाली ने अपने कामकाज के संचालन के लिए उपनियम बनाए हैं और नियम 60 से 71 में अध्यक्ष की शक्तियों को गिनाया गया है। नियम 66

निम्नानुसार है:-

66. राष्ट्रपति 40 रुपये प्रति माह के वेतन वाली सभी नियुक्तियों को मंजूरी दे सकते हैं और नगरपालिका समिति के संदर्भ के बिना कदाचार या कर्तव्य की लापरवाही या किसी अन्य चूक के लिए इस तरह से नियुक्त किसी भी सेवक को बर्खास्त कर सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी भी व्यावसायिक उप-नियम के तहत याचिकाकर्ता की सेवाओं को बर्खास्त करने या समाप्त करने की कार्यवाही नहीं कर सकते थे क्योंकि वह प्रति माह 40 रुपये से अधिक का वेतन ले रहे थे। निलंबन, आरोप पत्र दाखिल करने और जांच कराने की कार्रवाई नगरपालिका समिति को एक बैठक में करनी थी। राष्ट्रपति खुद याचिकाकर्ता को निलंबित नहीं कर सकते या आरोप पत्र दायर नहीं कर सकते या जांच नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए कोई आपात स्थिति नहीं थी, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता थी। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित था। इसके संबंध में नगरपालिका समिति की बैठक बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. राष्ट्रपति द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई चार्जशीट को भी इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि प्रस्तावित सजा का उल्लेख उसमें किया गया था। सजा देने वाला प्राधिकारी, आरोप-पत्र की तामील करते समय, सजा का प्रस्ताव नहीं कर सकता है जैसे कि आरोप साबित हो गए हों। खेमचंद बनाम भारत संघ और अन्य[1] के मामले में निर्भरता दिखाई है जिसमें कई आरोपों को बताने के बाद दस्तावेज निम्नानुसार निष्कर्ष निकाले गए: –

इसलिए आपको कारण बताने के लिए बुलाया जाता है कि आपको सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपको अपने उत्तर में यह भी बताना चाहिए कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से सुने जाना चाहते हैं या क्या आप बचाव पेश करेंगे। इस चार्जशीट के प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर जवाब सहायक रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीएसोसिएट्स, दिल्ली तक पहुंच जाना चाहिए।

इस दस्तावेज पर विचार करते हुए न्यायिक समिति के निर्णय पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने भारत के लिए उच्चायुक्त बनाम *आई. एम. लाल*[2] *मामले* कि सरकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का दूसरा अवसर उस चरण में पहुंचने के बाद दिया जाना चाहिए जहां आरोप स्थापित हो गए हों और सक्षम प्राधिकारी ने सिद्ध आरोपों की गंभीरता या अन्यथा पर अपना दिमाग लगाया हो और एक विशेष सजा का प्रस्ताव दिया हो। इसके बाद उनके लॉर्डशिप को निम्नानुसार देखा गया: –

"इस प्रक्रिया में संबंधित अधिकारी को कुछ आश्वासन देने की योग्यता भी है कि सक्षम प्राधिकारी उसके संबंध में खुले दिमाग रखता है। यदि आरोप सिद्ध होने से पहले सक्षम प्राधिकारी यह निर्धारित कर दे कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को कोई विशेष दंड दिया जाएगा, तो बाद वाला यह महसूस कर सकता है कि सक्षम प्राधिकारी ने उसके विरुद्ध एक राय बनाई है, सामान्यतया आरोप की विषय-वस्तु पर या, किसी भी दर पर, दंड के संबंध में। इस पहलू से भी हमारे द्वारा अपनाया गया निर्माण न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के अनुरूप प्रतीत होता है कि न्याय न केवल किया

[1] A.I.R 1958 S.C.300
[2] 75 I.A 225

जाना चाहिए, बल्कि किया जाना भी देखा जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद, गौरी पीआर घोष बनाम *पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य*[3] कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश (बीसी मित्रा, जे) *में निर्णय लिया*:

उन्होंने कहा, 'जिन सिद्धांतों के आधार पर कारण बताओ नोटिस में केवल आरोप लगाने की आवश्यकता होती है, न कि दोष का निष्कर्ष या दोष साबित होने पर दी जाने वाली सजा के प्रस्ताव की, वे अच्छी तरह से तय हैं और इस फैसले में मैंने पहले भी उन पर चर्चा की है. इन सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि आरोप साबित होने तक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में एक खुला दिमाग रखा जाना चाहिए। यदि इस तरह का खुला दिमाग नहीं रखा जाता है, लेकिन जांच इस धारणा पर की जाती है कि सरकारी कर्मचारी उस अपराध का दोषी है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, और यह भी कि वह एक विशेष सजा के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसी जांच को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाना चाहिए। इन आधारों पर न्यायालयों द्वारा जारी नोटिस को खारिज कर दिया गया था जिसमें न केवल एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोपों का उल्लेख किया गया था, बल्कि उसके अपराध के बारे में एक निष्कर्ष और प्रस्तावित सजा का एक बयान भी शामिल था।

यह सच है कि इस मामले में एक दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए कहा गया था कि बर्खास्तगी का जुर्माना उस पर क्यों न लगाया जाए। लेकिन, मेरे विचार से, पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट के बाद इस तरह के कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले कारण बताओ नोटिस को पूरी तरह से अवैध होने से नहीं बचाया जा सकता है। सिद्धांत में अंतर्निहित सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है, अर्थात्, न केवल एक सरकारी कर्मचारी के अपराध के सवाल पर, बल्कि आरोप साबित होने पर लगाए जाने वाले दंड के सवाल पर भी खुले दिमाग से रखा जाना चाहिए। सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाता है यदि एक कारण बताओ नोटिस, जिसमें न केवल आरोप, बल्कि ड्यूनिशमेंट रोपोज़ का भी उल्लेख किया गया है। एमवी के विचार में, ऊपर चर्चा किए गए कई मामलों में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कारण बताओ नोटिस को खराब माना जाना चाहिए।

5. राष्ट्रपति नगरपालिका समिति के प्रस्ताव के बिना खुद को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने उनके समक्ष उपस्थित होने या पूछताछ में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसलिए कि राष्ट्रपति द्वारा की गई पूछताछ अमान्य थी और 15 सितंबर, 1966 की उनकी रिपोर्ट भी अमान्य है। नगरपालिका समिति का प्रस्ताव 19 सितंबर, 1966 को पारित हुआ। उस रिपोर्ट के आधार पर भी रिपोर्ट के साथ आता है। नगरपालिका समिति का प्रस्ताव 7 अगस्त, 1966 को पारित किया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ राष्ट्रपति द्वारा पारित निलंबन के आदेश को साबित करना भी बुरा था और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उप-विभागीय कार्यालय ने याचिकाकर्ता की अपीलों से निपटते हुए तथ्यों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में स्थापित नहीं किया। उन्होंने उल्लेख किया है

[3] 1968 S.L.R 625

कि म्यूनिसिपल कमेटी ने याचिकाकर्ता को 25 जून, 1966 को एक आरोप-पत्र दिया, जबकि आरोप पत्र अकेले राष्ट्रपति द्वारा नगरपालिका समिति के संदर्भ के बिना जारी किया गया था। अधिनियम की धारा 35 के तहत याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई को समिति की अगली बैठक में अनुमोदित किया जाना था। कानून की इस आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया गया। 26 मई, 1966 के बाद नगरपालिका समिति की पहली बैठक 28 मई, 1966 को हुई थी, लेकिन उसमें राष्ट्रपति द्वारा 25 मई को पारित निलंबन के आदेश को मंजूरी देने वाला कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। अगली बैठक 28 जून, 1966 को आयोजित की गई थी। जिसमें कोरम के अभाव में कोई कार्य नहीं किया जा सकता था । तीसरी बैठक 5 जुलाई, 1966 को आयोजित की गई थी, जिसमें निलंबन का आदेश पुष्टि के लिए रखा गया था, लेकिन समय की कमी के कारण पुष्टि नहीं की गई थी। 7 अगस्त, 1966 को आयोजित बैठक में आदेश की पुष्टि की गई। अधिनियम की धारा 35 में निहित वैधानिक जनादेश के उल्लंघन के लिए, निलंबन के आदेश की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव कानून में खराब है।

6. याचिकाकर्ता के वकील ने अंत में तर्क दिया है कि जांच पर राष्ट्रपति की रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ता को प्रस्तावित सजा के खिलाफ कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और नगरपालिका समिति ने 19 सितंबर, 1966 को याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किए बिना या उसके बचाव में उसे सुने बिना प्रस्ताव पारित किया था। अधिकांश सदस्यों ने राष्ट्रपति की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिन्होंने इसे अपने स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित किया था, न कि उनके द्वारा दर्ज किए गए किसी भी सबूत पर। राष्ट्रपति ने अपनी रिपोर्ट बनाते समय और याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते समय बाहरी मामलों को भी ध्यान में रखा, जिन्हें याचिकाकर्ता के सामने कभी नहीं रखा गया। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता को कभी नहीं बताया गया कि उसकी बीमारी के बारे में वास्तविक प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहने पर सत्र न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी और इस तथ्य से निष्कर्ष निकाला गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा छुट्टी के लिए दिए गए आवेदन वास्तविक नहीं थे। एक अन्य कारक को ध्यान में रखा गया था कि उनके खिलाफ पुलिस के पास अवैध रिश्वत के संबंध में एक मामला लंबित था और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे और इसलिए आम जनता में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। याचिकाकर्ता के पास इन बाहरी विचारों का खंडन करने का कोई अवसर नहीं था, जिन्हें आरोप-पत्र में कभी नहीं रखा गया था। *अमर नाथ* बनाम *आयुक्त और अन्य*[4] में मैंने प्रशासक के आदेश को रद्द कर दिया था, जिन्होंने उस रिकॉर्ड को रखे बिना कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा था, मैसूर राज्य बनाम *मनचे गौड़ा*[5] मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के फैसले पर भरोसा करते हुए इसी आधार पर 15 सितंबर, 1966 को जांच अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति की रिपोर्ट और उसके आधार पर नगरपालिका समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

7. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाती है और 7 अगस्त को पारित नगरपालिका समिति का प्रस्ताव। 1966. याचिकाकर्ता

[4] 1969 C.L.J 484
[5] A.I.R 1964 S.C 506

को निलंबित करना और 19 सितंबर, 1966 को उसकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव, इसके द्वारा रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता की अपील खारिज करने के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को भी निरस्त किया जाता है। हालांकि, यह नगरपालिका समिति के लिए खुला होगा कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करे, अगर इसे उचित माना जाता है। वकील की फीस 100 रुपये।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।